vishikhamedia@gmail.com
विभिन्न विषयों पर आधारित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
RNI No. UTTHIN/2021/80704

_vishikhamedia/ vishikhamedia/

मूल्य:35 रूपये

vishikhamedia vishikhamedia.in

तीर निशाने पर

विशिखा

वर्ष:05 अंक:5 मई 2025 पृष्ठ:32

उत्तराखण्ड संस्करण

चारधाम यात्रा
एक पवित्र तीर्थ परिपथ

हिन्दू धर्म में चारधाम या छोटा चारधाम, हिमालय की गोद में स्थित एक अत्यंत पावन तीर्थ यात्रा मार्ग है। यह यात्रा उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के तीन जिलों कृ उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में फैली हुई है। इस यात्र के चार प्रमुख तीर्थ स्थल हैंः बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री।

विशिखा

विशिखा न्यूज़ 24x7

आपकी बात, आपके साथ

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

अब डिजिटल एडिशन में भी उपलब्ध

www.vishikhamedia.in

अंदर

24

भीख मांगकर देश चला रहे पाकिस्तानी भारत से नफरत नहीं उससे बराबरी करें

पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री या सेना प्रमुख हुए वह भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलते और आतंकवादियों को संरक्षण देते रहे। आज भी यह सिलसिला जारी है।

05 पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते निलंबित किए, अब भारत कर सकता है एलओसी पार

10 क्या अबकी बंगाल बोलेगा जय श्रीराम या फिर खेला होबे?

13 वन नेशन वन इलेक्शन देशहित में क्रांन्तिकारी कदमः सीएम धामी

14 बीजेपी बनाम सपाः गौशाला और इत्र पार्क पर छिड़ी सियासी जंग

16 वक्फ संशोधन बिलय अखिलेश के रूख से पार्टी की हिन्दू ल बी एवं पिछड़े मुसलमानों में नाराजगी

18 अभिव्यक्ति की आजादी पर कभी सख्त तो कभी नरम सुप्रीम कोर्ट

20 घुसपैठियों के लिए आसान लांचिंग पैड नेपाल बॉर्डर के मदरसे

22 तीन साल में यूपी से खत्म हो जाएगी गरीबीः योगी

26 बिहार में लालू परिवार से हटकर राहुल तैयार कर रहे हैं कांग्रेस की सियासी जमीन

28 राहुल गांधी की विदेश में जहरीली जुबान, भारत की साख पर वार

30 सरकार ने ऑनलाइन स्कैम पर कसा शिकंजाय चार मोर्चों पर लिया एक्शन

विशिखा
तीर निशाने पर...
विशिखा
तीर निशाने पर...
अंक: 5 वर्ष:05, मई 2025
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रियल श्रीवास्तव
सम्पादक
अनिल कुमार श्रीवास्तव
डिजाइन
देवेन्द्र नेगी, उत्तराखण्ड
विशिखा
तीर निशाने पर...
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक **अनिल कुमार श्रीवास्तव** द्वारा **भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड** शिवदासपुरा, टौंक रोड़, जयपुर से छपवाकर एवं **विशिखा मीडिया** सी-29, शिवलोक कॉलोनी, लाडपुर-राजपुर रोड़, देहरादून 248008 उत्तराखण्ड से प्रकाशित

पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका मे प्रकाशित सामग्री के विषय मे अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव अवश्य भेजें। अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझावों को आप हमें vishikhamedia@gmail.com पर ई-मेल भी कर सकते हैं।
लेखकों से निवेदन है कि कृपया अपनी स्व-लिखित एवं मौलिक रचनायें ही भेजें। रचनाओं के साथ अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल एवं फोटो अवश्य भेजें। रचनाओं के छापने या न छापने का अधिकार संपादकीय मंडल का होगा। अस्वीकृत रचनायें लौटाई नहीं जाएंगी।
पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख एवं रचनाओं में संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। पत्रिका मे प्रकाशित आलेख एवं रचनायें लेखकों के निजी विचार हैं। प्रकाशित सामग्री के उपयोग करने से पूर्व में संपादक की लिखित सहमति आवश्यक है।
*किसी भी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।
*पत्रिका मे प्रकाशित कुछ चित्र, लेख एवं आंकड़ो को इन्टरनेट एवं अन्य वेबसाइट से लिया गया है।

विशिखा न्यूज़ 24x7
आपकी बात, आपके साथ

सम्पादक की कलम से

अनिल कुमार श्रीवास्तव

22 अप्रैल का वो मनहूस दिन जब जम्मू कश्मीर में पहलगाम के निकट बैसरन की वह ख□ू□बसूरत घाटी जो शमिनी स्विट्जरलैंडश भी कहलाती है, में सैकडों लोग अपने परिजनों के साथ आनंद ले रहे थे कि उसी वक्त दिन के करीब दो बजे अचानक घाटी में तड़-तड़ की आवाज के साथ गोलियों की बौछार शुरू हो गई, जिसमें देश विदेश से आये 28 पर्यटक मारे गये तथा करीब 20 पर्यटक घायल हो गये. जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पर्यटकों से उनका धर्म पूछ कर उन्हें गोली मारी गई. तथा मारे गये पर्यटक सिर्फ पुरुष थे. बैसरन घाटी में किया गया यह आतंकी हमला, न सिर्फ मानवता पर हमला था बल्कि पूरे देश पर हमला था. आर्टिकल 370 हटने के बाद बैसरन घाटी में हुए इस हमले से कश्मीर में न सिर्फ पर्यटन व्यवसाय पर फर्क पड़ेगा, बल्कि कश्मीर में चल रहे अमन शांति के प्रयासों को भी झटका लगेगा. हमले के तुरंत बाद सरकार द्वारा पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अन्दर देश छोड़ने के आदेश दिए गए, इससे साफ जाहिर है कि इस हमले में पड़ोसी देश पूरी तरह शामिल है.

पहलगाम में हुए इस हमले के बाद अब वक्त आ गया है कि सरकार आतंकवादियों एवं आतंकवाद में जो भी शामिल है उस पर कड़ी कार्यवाही करे, जिससे कश्मीर कई सालों से चला आ रहे आतंकवाद से मुक्त हो सके...

बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मृतक पर्यटकों को विनम्र श्रद्धांजलि...

शेष फिर....

पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते निलंबित किए, अब भारत कर सकता है एलओसी पार

यह फैसला पाकिस्तान की बौखलाहट का प्रतीक है और इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है।

पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। इसके बाद से ही पाकिस्तान में हलचल मच गई है और उसने ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जो उसके लिए खुद ही घातक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान भारत के साथ किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करने के अधिकार का प्रयोग करेगा। इसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है। यह फैसला पाकिस्तान की बौखलाहट का प्रतीक है और इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है।

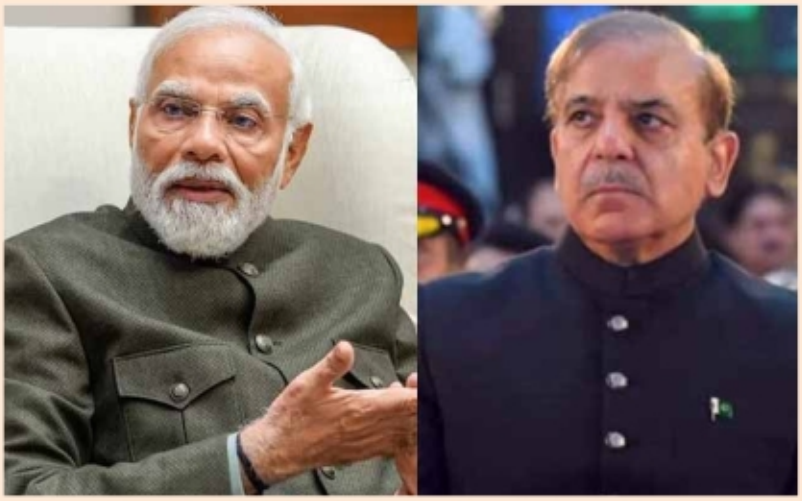

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान भारत के साथ किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करने के अधिकार का प्रयोग करेगा। इसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है।

शिमला समझौते के निलंबन का बड़ा असर

शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) की पवित्रता और बल प्रयोग से परहेज के लिए किया गया था। इसके निलंबन का सीधा अर्थ है कि अब भारत एलओसी पार करके कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत को पाकिस्तान–अधिकृत कश्मीर में अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाने का अवसर मिल सकता है।

कश्मीर मुद्दे पर भारत को मिलेगा नैतिक आधार

शिमला समझौता कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बनाए रखने की नींव था। अब जब पाकिस्तान खुद ही इसे निलंबित कर रहा है, तो भारत को कश्मीर पर अपनी नीतियों को वैश्विक मंच पर और मजबूती से रखने का तर्क मिल सकता है। भारत अब यह कहने की स्थिति में होगा कि पाकिस्तान ने ही संवाद के रास्ते को बंद किया है।

परमाणु सुरक्षा पर भी खतरा

भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु सुरक्षा को लेकर दो समझौते हैं, जिनका उद्देश्य अनजाने में होने वाले हमलों और गलतफहमियों को रोकना है। यदि पाकिस्तान वास्तव में सभी समझौते निलंबित कर देता है, तो इसका असर इन परमाणु सुरक्षा समझौतों पर भी पड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और जोखिम बढ़ सकता है।

कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को नुकसान

विशेषज्ञों के अनुसार, इन समझौतों को निलंबित करने का फैसला पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अंतरराष्ट्रीय साख को और नुकसान पहुंचाएगा। वैश्विक समुदाय इस कदम को गैर–जिम्मेदाराना और अस्थिरता बढ़ाने वाला मान सकता है, जिससे पाकिस्तान का अलगाव और गहरा हो सकता है।

तीर्थयात्रा और धार्मिक आधार पर विभाजन की कोशिश

1974 में हुए धार्मिक तीर्थयात्रा समझौते के तहत भारतीय श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। अब इन समझौतों के निलंबन से सिख तीर्थयात्रियों को विशेष रूप से नुकसान होगा। इसके साथ ही करतारपुर कॉरिडोर पर भी असर पड़ सकता है। वहीं, पाकिस्तान द्वारा सिख तीर्थयात्रियों को वीजा में छूट देने की घोषणा को विश्लेषक सांप्रदायिक विभाजन की एक रणनीति मान रहे हैं।

आर्थिक मोर्चे पर भी झटका

पाकिस्तान के इस कदम से भारत की निजी एयरलाइनों के उड़ान संचालन पर कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन इससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। उड़ान अधिकारों से होने वाली आमदनी से वह वंचित हो जाएगा, जो उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए और नुकसानदायक साबित होगा।

चारधाम यात्रा
एक पवित्र तीर्थ परिपथ

हिन्दू धर्म में चारधाम या छोटा चारधाम, हिमालय की गोद में स्थित एक अत्यंत पावन तीर्थ यात्र मार्ग है। यह यात्र उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के तीन जिलों कृ उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में फैली हुई है। इस यात्र के चार प्रमुख तीर्थ स्थल हैंः बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बद्रीनाथ न केवल छोटा चारधाम का भाग है, बल्कि यह भारत के प्रमुख चारधामों में उत्तर दिशा का धाम भी है। हालांकि इन चारों स्थानों का अपना-अपना महत्व है, फिर भी इन्हें एक साथ चारधाम के रूप में देखा जाता है।

भारत के चारधामों की संकल्पना के पीछे कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं, परन्तु यह चार पवित्र मंदिरों कृ पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ कृ का समूह माना जाता है, जिन्हें 8वीं शताब्दी में आदिशंकराचार्य ने एक सूत्र में बाँधा था। इनमें से प्रत्येक मंदिर का अपना विशेष स्थान है, परंतु बद्रीनाथ को विशेष रूप से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

हिमालय में स्थित छोटा चारधाम (जिसे अब शहिमालयी चारधामश कहा जाता है) में बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ (भगवान शिव का मंदिर), यमुनोत्री और गंगोत्री (देवी मंदिर) शामिल हैं। ये सभी स्थल हिन्दू धर्म में अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य में इन तीर्थ स्थलों को ष्छोटाष विशेषण दिया गया, जो आज भी प्रचलन में है। इन तीर्थों की यात्रा कठिन पर्वतीय मार्गों से होकर होती है, जिनकी ऊँचाई 4000 मीटर तक पहुँचती है।

1962 से पहले इन स्थानों की यात्रा अत्यंत कठिन थी, लेकिन भारत–चीन युद्ध के बाद जब इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियाँ बढ़ीं, तो यातायात की सुविधा भी सुधरने लगी। बाद में भ्रम से बचने के लिए ष्छोटाष शब्द को हटाकर इसे षहिमालयी चारधाम यात्राष कहा जाने लगा। आज यह हिन्दू तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन चुका है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। मानसून से पहले तक यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, जबकि बरसात के मौसम में यात्रा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि भूस्खलन का खतरा अधिक रहता है।

धार्मिक महत्व

हिन्दू धर्मग्रंथों के अनुसार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सबसे पवित्र स्थानों में से हैं। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों का दर्शन करने से न केवल इस जन्म के पाप धुलते हैं, बल्कि मनुष्य मोक्ष की ओर भी अग्रसर होता है। यह भी कहा गया है कि यह वह भूमि है जहाँ पृथ्वी और स्वर्ग का मिलन होता है। चारधाम यात्रा आमतौर पर यमुनोत्री और गंगोत्री से शुरू होती है, जहाँ से श्रद्धालु पवित्र जल लेकर केदारनाथ में भगवान केदारेश्वर का अभिषेक करते हैं। पारंपरिक यात्रा मार्ग इस प्रकार है:

हरिद्वार – ऋषिकेश – देवप्रयाग – टिहरी – धरासू – यमुनोत्री – उत्तरकाशी – गंगोत्री – त्रियुगनारायण – गौरीकुंड – केदारनाथ

इस मार्ग को हिन्दू धर्म की पवित्र परिक्रमा की तरह माना जाता है। एक वैकल्पिक मार्ग ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी और गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ पहुँचता है। केदारनाथ के निकट मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है।

यमनोत्री

यमुनोत्री मंदिर पवित्र पर्वत बांदरपूंछ की पश्चिमी चोटी पर स्थित है। यह चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। उत्तरकाशी जिले में स्थित जानकी चट्टी से लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई करके इस धाम तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ बना यमुना माता का मंदिर 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर समुद्र

तल से 3,291 मीटर की ऊँचाई पर है, जबकि इसके पीछे स्थित बांदरपूंछ पर्वत की ऊँचाई 6,315 मीटर है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुना सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन थीं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यमुना में स्नान करता है, यमराज उस पर कठोर नहीं होते। यमुना नदी का वास्तविक उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर है, जो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर 4,421 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। मंदिर के पास कई गर्म जलकुंड हैं जिनमें सूर्य कुंड प्रमुख है। मान्यता है कि सूर्य देव ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद स्वरूप इस गर्म जलधारा को प्रकट किया। श्रद्धालु इसमें चावल और आलू बाँधकर पकाते हैं और इन्हें प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। यहाँ एक पवित्र शिला को षदिव्य शिलाष कहा जाता है, जिसकी पूजा यमुना माता की पूजा से पहले की जाती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और माता यमुना की मूर्ति को खरसाली गांव में शनिदेव मंदिर में स्थापित किया जाता है।

- ऊँचाईः 10,804 फीट
- दर्शन समयः सुबह 6रू00 से रात 8रू00 बजे तक
- यात्रा का श्रेष्ठ समयः मई–जून और सितंबर–नवंबर
- दर्शनीय स्थलः दिव्य शिला, सूर्य कुंड, सप्तऋषि कुंड
- पहुँच मार्गः ऋषिकेश – नरेंद्रनगर – चम्बा – ब्रह्मखाल – बरकोट – स्यानाचट्टी – हनुमानचट्टी – फूलचट्टी – जानकीचट्टी – यमुनोत्री (6 किमी ट्रेक)

गंगोत्री

गंगोत्री समुद्र तल से 9,980 फीट की ऊँचाई पर स्थित है और यह वही स्थान है जहाँ से भागीरथी नदी (गंगा) का प्रवाह आरंभ होता है। गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है और देवी गंगा को समर्पित है।

पौराणिक कथा के अनुसार, राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया जिससे देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं। लेकिन उनके तीव्र प्रवाह से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर उसे धीरे–धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया।

माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में राजा माधोसिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर लगभग 20 फीट ऊँचा है और सफेद पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर के पास स्थित भागीरथ शिला वह स्थान है जहाँ राजा भागीरथ ने तपस्या की थी। यहाँ देवी गंगा के साथ–साथ यमुना, शिव, सरस्वती, अन्नपूर्णा और महादुर्गा की भी पूजा की जाती है। सर्दियों में गोवर्धन पूजा के दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और माँ गंगा की मूर्ति को हरसिल के पास मुखबा गांव में लाया जाता है।

- ऊँचाई: 11,200 फीट
- दर्शन समय: सुबह 6:15 से दोपहर 2:00 और फिर दोपहर 3:00 से रात 9:30 तक
- यात्रा का श्रेष्ठ समय: मई–जून और सितंबर–नवंबर
- दर्शनीय स्थल: भागीरथ शिला, भैरव घाटी, गौमुख, जलमग्न शिवलिंग
- पहुँच मार्ग: यमुनोत्री – ब्रह्मखाल –उत्तरकाशी – नेताला – मनेरी –गंगनानी – हरसिल – गंगोत्री
- गौमुख ग्लेशियर (गंगा का वास्तविक स्रोत) गंगोत्री से 19 किमी ट्रेक पर स्थित है।

केदारनाथ

केदारनाथ समुद्र तल से 11,746 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास बसा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, यमुनोत्री से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है।

पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान विष्णु मानव कल्याण हेतु पृथ्वी पर आए और सबसे पहले उन्होंने बद्रीनाथ को अपना निवास बनाया। वह स्थान पहले भगवान शिव का था, लेकिन उन्होंने वह स्थान त्याग कर केदारनाथ को अपना नया निवास बना लिया। इस कारण पंच केदार में केदारनाथ को विशेष स्थान प्राप्त है और यह स्थान त्याग की भावना का प्रतीक माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ आदि शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में समाधि ली थी। उन्होंने ही वीर शैव को केदारनाथ का रावल (मुख्य पुजारी) नियुक्त किया था। आज मंदिर का संचालन 337वें रावल द्वारा उखीमठ से किया जाता है, जहाँ सर्दियों में भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित किया जाता है।

गुप्तकाशी के पंडितगण भी मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं और प्रशासनिक दृष्टिकोण से मंदिर क्षेत्र को अलग–अलग हिस्सों में बांटा गया है।

केदारनाथ मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से भी अनोखा है। यह कात्युरी शैली में बना है और इसके निर्माण में बड़े भूरे पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मंदिर के ऊपर लकड़ी की छत और शिखर पर सोने का कलश है। मुख्य द्वार पर नंदी की विशाल प्रतिमा है।

यह चारधाम यात्रा का तीसरा प्रमुख धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा मानी जाती है। किंवदंती के अनुसार, महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने शिव की खोज में निकले। शिव पांडवों से मिलने नहीं चाहते थे, इसलिए वे बैल का रूप लेकर केदार में अंतर्ध्यान हो गए। भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली, और भगवान शिव पाँच स्थानों पर प्रकट हुए दृ केदारनाथ (पीठ), तुंगनाथ (भुजाएं), रुद्रनाथ (मुख), मध्यमहेश्वर (नाभि), और कल्पेश्वर (जटा)। इन पाँचों स्थानों को पंचकेदार कहा जाता है।

- ऊंचाई: 11,755 फीट
- सर्वश्रेष्ठ समय: मई–जून और सितंबर–नवंबर
- दर्शन समय: दोपहर 3:00 से 5:00 बजे तक बंद और बाकी समय खुला
- घूमने के स्थान: भैरवनाथ मंदिर, वासुकी ताल (8 किमी ट्रेक), त्रिजुगी नारायण आदि
- कैसे पहुंचे: गौरीकुंड तक वाहन से पहुँचा जा सकता है, वहाँ से 16 किमी की ट्रेकिंग करनी होती है। हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है।
- यात्रा मार्ग: रुद्रप्रयाग – गुप्तकाशी – फाटा – रामपुर – सीतापुर – सोनप्रयाग – गौरीकुंड – केदारनाथ (16 किमी ट्रेक)

बद्रीनाथ

बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 10,276 फीट की ऊँचाई पर स्थित है और यह नर और नारायण पर्वतों के मध्य बसा है। अलकनंदा नदी इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु यहाँ ध्यान में लीन रहते हैं। देवी लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए खुद को बैर (बदरी) वृक्ष में परिवर्तित कर लिया था। इसी वजह से यह स्थान बद्रीनाथ कहलाया।

मंदिर का निर्माण लगभग दो सौ वर्ष पूर्व गढ़वाल के राजा द्वारा करवाया गया था, जो शंकु आकृति में बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। मंदिर में विष्णु जी की एक मीटर लंबी शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति है, जिसे स्वयंभू माना गया है। इसके साथ नर–नारायण, लक्ष्मी, शिव–पार्वती, गणेश की मूर्तियाँ भी हैं।

आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था।

कथा अनुसार, भगवान विष्णु एक शांत स्थान की खोज में यहाँ आए और ध्यान में लीन हो गए। ठंड से बचाने के लिए देवी लक्ष्मी ने बदरी वृक्ष का रूप धारण किया। इस स्थान को तब से बद्रीकाश्रम कहा गया।

चारधाम यात्रा का यह अंतिम और सबसे पवित्र धाम माना जाता है। हर साल यहाँ

लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सर्दियों में, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान विष्णु की मूर्ति को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थापित किया जाता है।

- ऊंचाईः 10,170 फीट
- सर्वश्रेष्ठ समयः मई–जून और सितंबर–नवंबर
- दर्शन समयः सुबह 4:30 से दोपहर 1:00 बजे तक और शाम 4:00 से रात 9:00 बजे तक
- घूमने के स्थानः तप्त कुंड, चरण पादुका, व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, वसुधारा जलप्रपात आदि
- कैसे पहुंचेः सड़क मार्ग या केदारनाथ से हेलीकॉप्टर द्वारा पहुँचा जा सकता है
- यात्रा मागर्रू केदारनाथ – रुद्रप्रयाग – कर्णप्रयाग – नंदप्रयाग – चमोली – बिरही – पीपलकोटी – जोशीमठ – बद्रीनाथ

पौराणिक मान्यता

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब देवी गंगा ने मानवता के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित होने की स्वीकृति दी, तो देवताओं में हलचल मच गई, क्योंकि पृथ्वी गंगा के तीव्र वेग को सहन करने में असमर्थ थी। देवी गंगा ने स्वयं को 12 धाराओं में विभाजित कर लिया। इन्हीं धाराओं में से एक अलकनंदा है, जो बाद में भगवान विष्णु की तपोभूमि बनी और आज उसे बद्रीनाथ कहा जाता है। बद्रीनाथ 'पंच बद्री' में से एक है।

पंच बद्री

योगध्यान बद्री दृ यह स्थल समुद्र तल से 1920 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और इसकी ऐतिहासिकता लगभग 15,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है।

मुख्य दर्शनीय स्थल

तप्त कुंडः अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है, जिसमें पूजा से पहले श्रद्धालु स्नान करते हैं। कहा जाता है कि इसका जल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।

हेमकुंड साहिबः यह पवित्र स्थल बद्रीनाथ से 43 किमी दूर, फूलों की घाटी के पास स्थित है। यह सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म में यहां ईश्वर ध्यान करते हुए समाधि प्राप्त की थी। पास में ही लक्ष्मण मंदिर है।

ब्रह्म कपालः अलकनंदा के तट पर स्थित यह स्थल हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा पितरों के तर्पण और श्राद्ध क्रिया के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है।

नीलकंठ चोटीः यह बर्फ से ढकी पर्वत चोटी बद्रीनाथ के ऊपर स्थित है और इसे गढ़वाल की रानी कहा जाता है।

माणा गांवः बद्रीनाथ से 4 किमी दूर स्थित यह भारत का अंतिम गांव है, जहाँ इंडो–मंगोलियन जनजाति निवास करती है। यहाँ व्यास गुफा, भीम पुल (सरस्वती नदी पर बना प्राकृतिक पुल), और वसुंधरा जलप्रपात जैसे दर्शनीय स्थल हैं।

माता मूर्ति मंदिरः बद्रीनाथ से 3 किमी दूर स्थित यह मंदिर भगवान बद्रीनाथ की माता को समर्पित है।

अलका पुरीः यह स्थान 15 किमी की दूरी पर स्थित है।

सतोपंथ झीलः यह त्रिकोणीय झील समुद्र तल से 4402 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। इसकी परिधि लगभग 1 किमी है और माना जाता है कि इसके तीन कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। यहां पहुँचना कठिन है। पास ही गोविंदघाट में अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम होता है तथा गुरुद्वारा स्थित है।

जोशीमठः बद्रीनाथ से 44 किमी दूर स्थित यह स्थान शरद ऋतु में भगवान बद्रीनाथ का विश्राम स्थल होता है। यह उन चार मठों में से एक है जिन्हें आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था।

पंच प्रयाग

पंच प्रयाग में पाँच पवित्र संगम स्थल शामिल हैं– देवप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान इन्हें भी देखा जा सकता है।

श्रीनगर (गढ़वाल)

यह गढ़वाल की प्राचीन राजधानी है और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ कमलेश्वर और किलकेश्वर जैसे मंदिर दर्शनीय हैं।

मंदिर खुलने का समय

बद्रीनाथ मंदिर बसंत पंचमी (फरवरी) के दिन खुलता है और विजयादशमी (अक्टूबर मध्य) को बंद हो जाता है। मंदिर दर्शन का समय सुबह 4 बजे से दोपहर तक और फिर अपराह्न 3 से रात 9 बजे तक होता है।

चारधाम यात्रा हेतु आवागमन के साधन

हवाई मार्गः यात्रा सामान्यतः दिल्ली या हरिद्वार से प्रारंभ होती है। निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट (देहरादून) है, जो दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई और कोचीन से जुड़ा हुआ है।

रेल मार्गः हरिद्वार देश के प्रमुख शहरों से रेल द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।

सड़क मार्गः राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा चारधाम मार्ग श्ऑल वेदर रोडश परियोजना के तहत सुदृढ़ किया जा रहा है।

चारधाम मार्ग पर प्रमुख ठहराव

चारधाम के साथ–साथ पंच प्रयाग और औली, चोपता जैसे लोकप्रिय स्थलों को यात्रा में शामिल किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण सुझाव

- चारधाम यात्रा अप्रैल–मई से नवंबर की शुरुआत तक ही संभव है।
- मानसून (जुलाई–अगस्त) में यात्रा से बचें: भूस्खलन और रास्ते बंद होने की संभावना रहती है।
- ऊनी कपड़े, प्राथमिक दवाइयां, पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी आदि) साथ रखें।
- पहाड़ों में सूर्यास्त के बाद यात्रा से बचें।
- स्वास्थ्य की जाँच और शारीरिक रूप से फिट रहना जरूरी है, खासकर केदारनाथ जैसे ऊँचाई वाले धामों के लिए।
- होटलों को अधिक अपेक्षाये न रखें, इनमें सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं लेकिन लक्जरी नहीं।
- पर्यावरण की रक्षा करें दृ पॉलीबैग और प्लास्टिक का उपयोग न करें।
- यात्रा से एक–दो महीने पहले होटल और पैकेज की बुकिंग कर लें।

क्या अबकी बंगाल बोलेगा जय श्रीराम या फिर खेला होबे?

2026 के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे-वैसे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी तनाव गहराता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी का पर्व अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह गया, बल्कि यह राज्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला एक अहम मौका बन गया है।

अजय कुमार, लखनऊ

बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और इस बार इसकी जड़ में है भगवान राम का नाम, जिसकी आस्था को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी चुनावी रणनीति के रूप में चुन लिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव जैसे–जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे–वैसे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी तनाव गहराता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी का पर्व अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह गया, बल्कि यह राज्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला एक अहम मौका बन गया है। रामनवमी के दिन जिस तरह बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने राज्य भर में तकरीबन 2000 शोभा यात्राएं निकालीं, उसने यह साफ कर दिया कि पार्टी 2026 के चुनाव में किस एजेंडे के साथ मैदान में उतरेगी। इन यात्राओं में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, हाथों में भगवा झंडे, तलवारें, जय श्रीराम के नारे और भगवा वस्त्रों में लिपटे

कार्यकर्ताओं की भीड़ ने यह संदेश दे दिया कि यह आस्था की नहीं, सियासत की भी यात्रा है।

बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल और शुभेंदु अधिकारी जैसे वरिष्ठ नेता इन आयोजनों का चेहरा बने, जिन्होंने मंच से सीधे–सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अग्निमित्रा पॉल ने यहां तक कहा कि राम शोभा यात्रा के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, केवल पुलिस को सूचित करना होता है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में राम मंदिर की आधारशिला रखकर ममता बनर्जी को सीधे उनके गढ़ में चुनौती दी। नंदीग्राम वही इलाका है जहां 2007 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलन ने ममता को सत्ता की ओर पहला बड़ा मौका दिया था और अब वही स्थान बीजेपी की रणनीति का आधार बन गया है।

बीजेपी इस बार किसी भ्रम में नहीं है। पार्टी को पता है कि पश्चिम बंगाल में उसने पिछले विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतकर अपनी सबसे बड़ी सफलता दर्ज की थी और अब वह उस आधार को और मजबूत करना चाहती है। 2016 के चुनाव में जहां बीजेपी को केवल 10.2 प्रतिशत वोट मिले थे, वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 38.1 प्रतिशत तक पहुंच गया था। यह उछाल केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श का संकेत है, जिसे बीजेपी और आरएसएस बखूबी भुनाना चाह रहे हैं। इसीलिए अब पार्टी ने हिंदुत्व को चुनावी हथियार के रूप में और भी धारदार बना दिया है।

रामनवमी की इन शोभा यात्राओं के पीछे केवल धार्मिक उत्साह नहीं था। यह सांस्कृतिक दावे और राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की एक योजनाबद्ध कोशिश थी। बंगाल के विभिन्न जिलों में जो यात्राएं निकाली गईं, उसमें भगवा रंग की स्पष्टता, जय श्रीराम के नारों की गूंज और हिंदू धर्म के प्रतीकों की भरमार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी अब बंगाल को भी उसी तरह हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना चाहती है, जैसा वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में कर चुकी है। पार्टी यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि बंगाल की धरती भी राम की है, यहां भी उनके भक्तों की संख्या कम नहीं है और वे अब राजनीतिक बदलाव की तैयारी में हैं।

बीजेपी की इस रणनीति के जवाब में ममता बनर्जी ने भी चुप्पी साधे रखने का रास्ता नहीं चुना। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बंगाल की संस्कृति को बाहरी तत्वों से खतरा है। उन्होंने दोहराया कि बंगाल, गुजरात या यूपी नहीं है। यहां की संस्कृति, भाषा, खानपान और जीवनशैली अलग है और उसे किसी बाहर से आई विचारधारा से बदलने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में भी इसी 'बाहरी बनाम बंगाली' नैरेटिव के सहारे बीजेपी को घेरने में कामयाबी पाई थी और अब वह उसी पथ को फिर से अपनाने जा रही हैं। बंगाली अस्मिता की बात कर ममता फिर से राज्य की जनता को यह संदेश देना चाहती हैं कि बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति इस राज्य की मिट्टी से मेल नहीं खाती।

तृणमूल कांग्रेस इस बार न सिर्फ अस्मिता की बात करेगी बल्कि ममता की प्रशासनिक ताकत को भी सामने रखेगी। रामनवमी के दौरान किसी भी बड़े हिंसक घटना का न होना, पुलिस की मौजूदगी और शांति बनाए रखना, यह सब ममता सरकार की ओर से एक संदेश है कि वह हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रख सकती हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने खुद कहा कि पिछले दो महीने से शोभा यात्राओं को लेकर पुलिस बल की तैयारी की जा रही थी और इसी वजह से किसी तरह की बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। ममता इसे अपनी सफलता के रूप में प्रचारित करेंगी और इसे बीजेपी की अराजकता के खिलाफ एक मजबूत प्रशासनिक प्रतिवाद के रूप में दिखाएंगी।

बीजेपी की रणनीति के तहत अब बंगाल के उन स्थानों को भी धार्मिक नक्शे में प्रमुखता से रखा जा रहा है, जिनका रामायण काल से कोई न कोई संबंध माना जाता है। बर्दवान का सुश्रवणगढ़, बांकुड़ा का गंधेश्वरी मंदिर और बीरभूम का गिरिधारीपुर जैसे स्थानों को राम या हनुमान से जोड़ते हुए एक नया धार्मिक विमर्श रचा जा रहा है। यह कोशिश बंगाल की मिट्टी को राममय करने की है, जिससे जनता को यह विश्वास दिलाया

जा सके कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान और भगवान राम में कोई विरोध नहीं है। बीजेपी के लिए यह सांस्कृतिक पुनःस्थापना का अवसर है और वह इसमें कोई चूक नहीं करना चाहती।

लेकिन यह लड़ाई केवल धार्मिक प्रतीकों तक सीमित नहीं रहेगी। टीएमसी के रणनीतिकार जानते हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता को केवल अस्मिता की राजनीति से रोका नहीं जा सकता, इसके लिए जमीनी मुद्दों पर भी काम करना होगा। इसलिए ममता बनर्जी का जोर विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी रहेगा। महिला मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ पहले से ही मजबूत है और वह इसे और भी मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही ममता यह भी चाहेंगी कि मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ एकजुट रहें, जैसा उन्होंने 2021 में किया था।

भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर हिन्दुत्व की राजनीति कर रही है। उसके सामने यह मजबूरी नहीं है कि हिन्दू वोटरों को खुश करने के चक्कर में उनके

रामनवमी की इन शोभा यात्राओं के पीछे केवल धार्मिक उत्साह नहीं था। यह सांस्कृतिक दावे और राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की एक योजनाबद्ध कोशिश थी। बंगाल के विभिन्न जिलों में जो यात्राएं निकाली गईं, उसमें भगवा रंग की स्पष्टता, जय श्रीराम के नारों की गूंज और हिंदू धर्म के प्रतीकों की भरमार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी अब बंगाल को भी उसी तरह हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना चाहती है,

हाथों से मुस्लिम वोटर निकल सकते हैं। क्योंकि बीजेपी को मुस्लिमों का साथ कभी मिलता ही नहीं है। वहीं ममता बनर्जी एक तरफ मुस्लिम वोटों को कांग्रेस या वामपंथी दलों पाले में जाने से बचाने में लगी हैं। वहीं हिन्दुओं को भी नाराज नहीं करना चाहती हैं। यही दुविधा ममता बनर्जी पर भारी पड़ रही है। राहुल गांधी आजकल पश्चिम बंगाल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनका ज्यादा फोकस मुस्लिम वोटरों पर है, इसको लेकर भी ममता बेचौन हैं। कांग्रेस यदि बंगाल में ठीकठाक लड़ती है तो इससे ममता बनर्जी की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है? वहीं बीजेपी मुस्लिम वोटों के बंटने पर फायदे में रहेगी बीजेपी का सियासी हमला हालांकि तीव्र है, लेकिन ममता की सरकार भी जवाब देने में उतनी ही तेज नजर आ रही है। राज्य में प्रशासनिक मजबूती, सांस्कृतिक गर्व और विकास के मिश्रण से वह यह संदेश देना चाहती हैं कि बंगाल की राजनीति का चेहरा बीजेपी नहीं, बल्कि तृणमूल ही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी हर धार्मिक पर्व, हर सांस्कृतिक अवसर को एक चुनावी मंच की तरह इस्तेमाल कर रही है। रामनवमी इसके लिए पहला पड़ाव था, आने वाले महीनों में दुर्गा पूजा, दीवाली, और अन्य त्योहारों को भी राजनीतिक रंग दिए जाने की पूरी संभावना है।

2026 का चुनाव अब केवल एक राजनीतिक मुकाबला नहीं रह गया, यह विचारधाराओं की जंग बन चुका है। एक ओर है राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश, दूसरी ओर है बंगाली अस्मिता की रक्षा की हुंकार। यह संघर्ष अब चुनावी मैदान तक सिमटा नहीं रहेगा, बल्कि हर गली, हर चौक, हर मंदिर, हर कॉलेज और हर पंचायत में महसूस किया जाएगा। जनता को अब तय करना है कि वे किस रास्ते पर जाना चाहते हैं राम के नाम पर भगवा राजनीति या ममता की नीली–हरी अस्मिता। यह फैसला केवल बंगाल की दिशा नहीं तय करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करेगा।

राजनीति के इस रामायण में हर दल अपने–अपने पात्रों को सजाने में जुटा है, लेकिन अंत में जनता ही है जो राम की भूमिका निभाएगी और सत्ता की संजीवनी किसे देनी है, यह फैसला करेगी। इतिहास गवाह है कि बंगाल कभी किसी के लिए आसान नहीं रहा और इस बार की जंग तो और भी पेचीदा और दिलचस्प होने जा रही है। जैसे–जैसे चुनाव नजदीक आएगा, यह संघर्ष और भी उग्र होगा और शायद इस बार राजनीति का असली चेहरा बंगाल से ही सामने आएगा।

वन नेशन वन इलेक्शन देशहित में क्रन्तिकारी कदम सीएम धामी

वन नेशन वन इलेक्शन देशहित में क्रन्तिकारी कदम सीएम धामी मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सभी को दिखानी होगी एकजुटता पीएम मोदी के नेतृत्व में देशहित में सब संभव वन नेशन वन इलेक्शन पर दृढ़ता से अपने विचार रखते हुए सीएम धामी ने कहा कि एक राष्ट्रएक चुनाव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यह देशहित में क्रान्तिकारी कदम है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव लोकतंत्र का पर्व होते हैं, लेकिन जब प्रत्येक वर्ष, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, बारबार चुनाव होते हैं, तो यह प्रक्रिया बोझ बन जाती है। उन्होंने कहा कि बारबार आचार संहिता लगने से विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बारबार चुनाव होने से चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक स्तर पर बारबार संसाधनों का अपव्यय होता है व सरकारी खजाने पर नकारात्मक असर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चुनावो के दौरान बड़ी संख्या में राज्य के शिक्षकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पुलिस बल और केंद्रीय बल के जवानों को उनके मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है, जिससे उनके मूल कार्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सबको एकजुटता दिखानी होगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय सर्वेक्षण विभाग सभागार देहरादून में स्वर्णिम देवभूमि फाउंडेशन द्वारा एक राष्ट्रएक चुनाव विषय पर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उत्तराखंड आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय प्रभारी श्री सुनील बंसल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री

नरेंद्र मोदी जी का लगभग 11 वर्षों का कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में पिछले एक दशक में जहां एक ओर देश में विकास और आर्थिक प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित हुए, वहीं अनेकों ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से भारत के लोकतंत्र को और भी अधिक मजबूती मिली। चाहे जीएसटी लागू करना हो, तीन तलाक की समाप्ति हो,कश्मीर से धारा 370 खत्म करना हो, सीएएएनआरसी का कानून बनाना हो, नारीशक्ति वंदन अधिनियम पारित करना हो या फिर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करना हो। इन सभी ऐतिहासिक निर्णयों ने भारत को एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रएक चुनाव के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि एक बार में चुनाव हों तो 12 हजार करोड़ रूपए तक की बचत होगी। हजारों करोड़ों की इस धन राशि को देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय रहेगा तो सभी कार्य निश्चित समय पर पूरे होंगे। चुनाव होने से वोटिंग टर्नआउट में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं वो बारबार वोट देने के लिए अपने गृह राज्य में जाने से कतराते हैं लेकिन जब तीनों स्तर के चुनाव एक साथ होंगे तो वो वोट देने अवश्य जाएँगे। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक तकनीक, चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जनता के सहयोग से इस संतुलन को पुनः स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अमेरिका, जापान, ब्राजील और स्वीडन जैसे देशों में एक साथ चुनाव की व्यवस्था हो सकती है तो क्या भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये व्यवस्था नहीं हो सकती आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जैसे दृढ़ और संकल्पित प्रधान सेवक हमारे पास हैं तो देश हित का कोई काम रुक जाए, ऐसा हो नहीं सकताद्य प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया जो ड्राफ्ट लोक सभा में पेश किया गया, वो बहुत ही गहन शोध और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में एकएक परिस्थिति का ध्यान रखा गया है कि कैसे सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू करनी है और लागू करने के बाद यदि किसी राज्य की सरकार बीच में भंग हो गई तो उस स्थिति में कैसे चुनाव होंगे। फिलहाल इस कानून को व्यापक विचार विमर्श हेतु संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ये एक राष्ट्रएक चुनाव की व्यवस्था भारत में अवश्य लागू होगी।

बीजेपी बनाम सपा: गौशाला और इत्र पार्क पर छिड़ी सियासी जंग

अजय कुमार, लखनऊ

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में गौशालाओं को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वे गौशालाएं बना रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सुगंध पसंद करती है, इसलिए उन्होंने इत्र पार्क बनाए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। बीजेपी ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया और कहा कि अखिलेश यादव की यह टिप्पणी हिन्दू परंपराओं का अपमान करने के बराबर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह बयान न केवल गाय के सम्मान के खिलाफ है, बल्कि यह हिंदू संस्कृति और आस्था पर हमला भी है। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति में उलझ चुकी है और इसी कारण इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं।

अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बयान ने उनकी पार्टी के भीतर भी विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कई नेता सार्वजनिक रूप से तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन पार्टी के अंदरखाने में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि गाय हमारी माता है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का मूल आधार ही समाज के सभी वर्गों का सम्मान करना है और ऐसे बयानों से पार्टी की छवि प्रभावित होती है।

अखिलेश यादव पहले भी कई बार अपने बयानों के कारण विवादों में रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने राणा सांगा को लेकर भी एक विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिससे उनकी पार्टी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा, उन्होंने औरंगजेब को लेकर भी कुछ ऐसा कहा था जिससे हिंदू मतदाताओं में नाराजगी देखी गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव अपनी राजनीति को बचाने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह रणनीति उनके परंपरागत यादव वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है।

यादव समाज का गौ–सेवा से पुराना रिश्ता रहा है। महाभारत काल से लेकर आज तक यादव समुदाय में गाय को लेकर विशेष सम्मान देखा गया है। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं यादव कुल में जन्मे थे और उनका जीवन गौ–सेवा में

ही बीता। आज भी देश में यादव समुदाय गाय को लेकर अपनी भावनाएं प्रकट करता है और उसे अपनी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा मानता है। मुलायम सिंह यादव भी गौ–सेवा में विश्वास रखते थे और उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर कहा था कि उनके पास जितनी गायें हैं उतनी किसी और नेता के पास नहीं होंगी। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गौशालाओं को लेकर कई योजनाएं भी बनाई थीं।

अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे हिन्दू आस्था का अपमान बताते हुए कहा कि गाय भारतीय संस्कृति की आत्मा है और उसका अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बयान केवल राजनीति से प्रेरित है और यह समाज को बांटने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस बयान की आलोचना की और कहा कि अखिलेश यादव अब पूरी तरह से अपनी राजनीतिक दिशा भूल चुके हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में उलझे हुए हैं।

अखिलेश यादव का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी अपनी हिंदुत्व की राजनीति को और मजबूत कर रही है और अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी को और आक्रामक बना दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव के इस बयान से उनका परंपरागत यादव वोट बैंक भी उनसे खिसक सकता है।

गाय और गौशालाओं को लेकर अखिलेश यादव के इस बयान से समाज के कई वर्गों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में आज भी गौ–सेवा को विशेष महत्व दिया जाता है और इसे सनातन धर्म का हिस्सा माना जाता है। गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं और खेती में किया जाता है। कई भारतीय घरों में आज भी गौ–सेवा की परंपरा कायम है। ऐसे में

अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे हिन्दू आस्था का अपमान बताते हुए कहा कि गाय भारतीय संस्कृति की आत्मा है और उसका अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बयान केवल राजनीति से प्रेरित है और यह समाज को बांटने की कोशिश है।

अखिलेश यादव का बयान न केवल राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है, बल्कि यह समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकता है।

समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने अखिलेश यादव से अपील की है कि वे अपने बयान को स्पष्ट करें, ताकि इससे होने वाले संभावित नुकसान से बचा जा सके। यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव इस पर सफाई दें और कहें कि उनके बयान को तोड़–मरोड़ कर पेश किया गया है। यह पहला मौका नहीं होगा जब अखिलेश यादव को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी हो। इससे पहले भी वे कई बार अपने बयानों से पलट चुके हैं।

बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। बीजेपी के नेता इसे हिंदू आस्था से जोड़कर दिखा रहे हैं और अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले ही समाजवादी पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाना जाता है और अब इस बयान के बाद बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है। बीजेपी की आईटी सेल इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार कर रही है और अखिलेश यादव की छवि को नुकसान पहुंचाने का हरसंभव प्रयास कर रही है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव वोट बैंक का विशेष महत्व है। बीजेपी लंबे समय से यादवों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने यह संदेश दिया था कि वे यादवों को भी सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार में भी यादव समुदाय से कई मंत्री बनाए गए हैं। इन सबके जरिए बीजेपी यह बताना चाहती है कि समाजवादी पार्टी की तरह ही बीजेपी भी यादवों की हितैषी है। ऐसे में यदि अखिलेश यादव इसी तरह विवादित बयान देते रहे, तो यादव वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में राजनीति के जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जो समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। गाय भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, और उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। राजनीति में धर्म और आस्था से जुड़े मुद्दों पर बयान देते समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे लोगों की भावनाओं से सीधे जुड़े होते हैं।

अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और समाजवादी पार्टी इस पूरे विवाद को कैसे संभालती है। क्या अखिलेश यादव इस बयान से पीछे हटेंगे, या फिर अपने बयान पर कायम रहेंगे, यह देखना बाकी है। फिलहाल बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही और आने वाले चुनावों में यह बयान सपा के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

समाजवादी पार्टी के लिए यह समय राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। अगर अखिलेश यादव सही रणनीति नहीं अपनाते हैं, तो आगामी चुनावों में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी पूरी तरह से हिंदुत्व की राजनीति को धार देने में लगी हुई है और ऐसे में अखिलेश यादव के इस तरह के बयान बीजेपी को ही फायदा पहुंचा सकते हैं। अंततः यह स्पष्ट है कि राजनीति में बयानबाजी करते समय नेताओं को सतर्क रहना चाहिए, ताकि उनके शब्द समाज में सकारात्मक संदेश

वक्फ संशोधन बिलय

अखिलेश के रूख से पार्टी की हिन्दू लॉबी एवं पिछड़े मुसलमानों में नाराजगी

संजय सक्सेना, लखनऊ

मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को कानून बनाकर एक नया इतिहास लिख दिया है। इन संशोधनों को 'उम्मीद' का नाम दिया गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनैतिक दलों के साथ–साथ समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिये मोदी सरकार द्वारा लाये गये वक्फ संशोधन का खुलकर विरोध किया, लेकिन मुस्लिम राजनीति को करीब से जानने वाले कुछ लोगों को लग रहा है कि इससे सपा को फायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि मुस्लिमों में कई पिछड़ी बिरादरियां इस बिल का समर्थन भी कर रही हैं। इसमें ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल, जमीयत हिमायत उल इस्लाम और पसमांदा मुस्लिम महाज जैसे मुस्लिम संगठन शामिल हैं, जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है. इन संस्थाओं ने वक्फ बोर्डों पर इतने सालों से काबिज रहे लोगों से तीखे सवाल पूछे हैं. इन संगठनों का दावा है कि वक्फ बिल पास होने से सिर्फ वो मुसलमान परेशान हैं जो खुद वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर कब्जा किए बेठे हैं. पसमांदा (पिछड़े) मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह संगठन वक्फ बिल के पक्ष में है. सितंबर 2024 में जेपीसी की बैठक में इसने बिल को 85 प्रतिशत मुस्लिमों के लिए फायदेमंद बताया था। इस संगठन का कहना है कि यह बिल वक्फ बोर्ड में सुधार लाकर हाशिए पर पड़े मुस्लिमों को लाभ पहुंचाएगा, लेकिन यह बात समाजवादी पार्टी जैसे दलों के नेताओं को समझ में नही आ रही है।

यही वजह है लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिल के विरोध में अपने मुस्लिम सांसदों की 'फौज' उतार दी। आजमगढ़ के सांसद धमेन्द्र यादव, संभल के सांसद जिया–उर–रहमान बर्क, कैराना की सासंद इकरा हसन चौधरी, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने बिल के विरोध में मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, तो राज्यसभा में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बिल के विरोध में मोर्चा संभाला। इनमें से एक मुस्लिम सांसद ने तो चर्चा के दौरान धमकी भरी आवाज में यहां तक कह दिया कि मुसलमान इस कानून को नहीं मानेंगे। सपा की सांसद इकरा चौधरी ने बहस के दौरान झूठा आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में ईद पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी गई।

समाजवादी पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जिन सांसदों को बोलने का

मौका दिया था, उसमें या तो यादव कुनबे से जुड़े सांसद थे या फिर मुस्लिम सांसद। सपा की तरफ से सात सांसदों ने अपनी बात विस्तार से रखी जिसमें चार मुसलमान सांसद थे और तीन मुलायम कुनबे के सांसद। समाजवादी पार्टी ने अपने 37 सांसदों में से जिन सांसदों को बहस के लिये चुना उसमें एक भी यादव कुनबे से इत्तर या फिर गैर मुस्लिम सांसद नहीं था। इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी को शक की नजर से देखा जा रहा है। सपा के हिन्दू सांसदों के बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। पार्टी के बेइंतहा मुस्लिम प्रेम के चलते हिन्दू बाहुल्य लोकसभा सीटों से चुनाव जीतने वाले हिन्दू सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गये हैं। इस बात का अहसास तब और मजबूत हो गया जब वक्फ बिल पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम परस्त रवैये के बीच अयोध्या लोकसभा चुनाव सीट से जीतने वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद अचानक रामलला के दर्शन करने पहुंच गए, जबकि अभी तक अखिलेश अपने इस सांसद को पार्टी का मुखौटा बनाये घूम रहे थे। अवधेश चुनाव जीतने के 11 महीने बाद रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यह तब हुआ जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 'इशारे' पर अभी तक अवधेश प्रसाद रामलला के मंदिर जाने से बचते रहे थे, उन्हें भी लगने लगा है कि यदि उनकी भी छवि मुस्लिम परस्त बन गई तो हिन्दू बाहुल्य रामलला की नगरी में आगे सियासत करना उनके लिए आसान नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के अन्य उन सांसदों की भी है जो 2024 के आम चुनाव में हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव जीत कर आये थे। इसी के चलते इन सांसदों का वक्फ बिल के समर्थन में कोई बयान भी नहीं आया है।

बात इससे आगे की कि जाये तो समाजवादी पार्टी ने खासकर उन सांसदों को बिल का विरोध करने का मौका दिया जिनकी छवि पहले से ही काफी विवादित है और इन सांसदों की पहचान हिंदुओं और उनके देवी देवताओं को अपमानित करने वाली रही हैं। एक–एक कर इन सांसदों की बात की जाये तो संभल के सांसद जिया–उर–रहमान के दिवंगत सांसद पिता अक्सर हिन्दुओं के खिलाफ जहर उगला करते थे। उन्हीं की तर्ज पर जिया उर रहमान बर्क चल रहे हैं। नवंबर 2024 में संभल की शाही मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। इस घटना के बाद, पुलिस ने सपा सांसद जिया उर रहमान के खिलाफ उपद्रव की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया था। बर्क पर बिजली चोरी और संभल हिंसा के दौरान एक वर्ग विशेष के लोगों को भड़काने का भी आरोप है।

इसी तरह से कैराना की सपा सांसद इकरा हसन चौधरी भले ही सांसद हों, लेकिन उनकी स्वयं की पृष्ठभूमि कोई राजनैतिक नहीं है। समाजवादी पार्टी कैराना की सांसद इकरा हसन के भाई, नाहिद हसन, का विवादों से गहरा नाता रहा है। वह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उनके खिलाफ लगभग डेढ़ दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप भी शामिल हैं. नाहिद की दबंगई के कारण कई हिन्दू परिवार कैराना से पलायन को मजबूर हो गये थे। जनवरी 2022 में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले, नाहिद हसन को शामली में गिरफ्तार किया गया था। जिस कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाये, इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनकी बहन इकरा हसन को कैराना सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करा दिया। आज इकरा भाई की सोच को ही आगे बढ़ा रही हैं।

समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी भी वक्फ बिल के दौरान मोदी सरकार पर खूब बरसे थे, अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। गाजीपुर के आसपास मुख्तार की तूती बोलती थी, कहा यह जाता था कि मुख्तार के पास मसल पॉवर थी तो इसके पीछे दिमाग अफजाल अंसारी का रहता था। सपा के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने 12 फरवरी 2025 को शादियाबाद में संत रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में महाकुंभ स्नान पर विवादित टिप्पणी की। इससे पहले भी उन्होंने साधु–संतों और धार्मिक प्रथाओं पर टिप्पणियां की थी, जिनसे विवाद उत्पन्न हुआ था। मुख्तार अंसारी की मौत के समय अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जिलाधिकारी से भी अभद्रता करते देखा गया था।

समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी भी वक्फ बिल के खिलाफ खूब दहाड़े थे, नदवी को अखिलेश ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की इच्छा के खिलाफ लोकसभा का टिकट दिया था। नदवी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान में जेल में बंद आजम का बिना नाम लिये कहा था कि जेल सुधार गृह होती है। जिससे पार्टी के भीतर तनाव बढ़ा। आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने नदवी के इस बयान की आलोचना की। घटनाओं से समाजवादी पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद व रामपुर की राजनीति में तनाव स्पष्ट होता है। नदवी का पारिवारिक जीवन भी विवादों से भरा है। नदवी का अपनी एक बीवी से तलाक का मुकदमा चल रहा है, उसे वह कोर्ट के आदेश के बाद भी गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं।

समाजवादी पार्टी ने वक्फ बिल पर चर्चा के लिये जिन सांसदों को आगे किया, उसके चलते ही सपा पर आरोप लग रहा है कि अब उसके आइडियल मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, दाराशिकोह, कृष्ण भक्त रसखान, वीर अब्दुल हमीद (परमवीर चक्र विजेता), बिस्मिल्लाह खां (शहनाई वादक), डॉ. अब्दुल कलीम अजीज (इतिहासकार), अब्दुल कय्यूम अंसारी (स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता), शाह मुबारक अली (शिक्षाविद और समाज सुधारक), जोहरा सहगल (अभिनेत्री और नृत्यांगना), कैप्टन अब्बास अली (स्वतंत्रता सेनानी) जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे। आजादी के बाद समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहे। पर इन हस्तियों के नाम पर समाजवादी पार्टी में कोई चर्चा नहीं होती है। बल्कि बाबर, औरंगजेब, बाहुबली अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी, यासीन मलिक, दाऊद, याकूब मैनन, अफजल गुरू जैसे

अभिव्यक्ति की आजादी पर कभी सख्त तो कभी नरम सुप्रीम कोर्ट

21 जनवरी 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह एफआईआर उनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप को लेकर दर्ज की गई थी।

संजय सक्सेना, लखनऊ

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के बाद विभिन्न क्षेत्रों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सौहार्द, और न्यायिक प्रक्रियाओं के बीच संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण बहस का केंद्र बन गया है। बता दें 21 जनवरी 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह एफआईआर उनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप को लेकर दर्ज की गई थी, जिसमें बैकग्राउंड में 'ऐ खून के प्यासे बात सुनो' कविता चल रही थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि यह कविता भड़काऊ है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती है।

कुछ विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना यह तर्क देते हुए की कि न्यायपालिका को ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए जहां सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह निर्णय कानून के समक्ष सभी के लिए समानता के सिद्धांत के अनुरूप है। उधर, कानूनी विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना है। उन्होंने कहा कि यह मामला पुलिस और न्यायपालिका के लिए एक संकेत है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामलों में संवेदनशीलता और समझ की आवश्यकता है। इसी तरह से कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थन में आवाज उठाई, यह कहते हुए कि उनकी कविता का उद्देश्य अहिंसा और प्रेम का संदेश देना था, न कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना। उन्होंने यह भी कहा कि कला और साहित्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

बात सोशल मीडिया की कि जाये तो यहां पर जनता की प्रतिक्रियाएं मिश्रित रहीं। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया, जबकि अन्य ने चिंता व्यक्त की कि इस तरह के निर्णय

सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं।

दरअसल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, यह अधिकार पूर्णतः असीमित नहीं हैय अनुच्छेद 19(2) के तहत, राज्य को कुछ निश्चित परिस्थितियों में इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, जैसे कि देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि, या अपराध के लिए उकसाना। 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की खंडपीठ ने निर्णय दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे दूसरों की प्रतिष्ठा के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा,'हमने माना है कि दंडात्मक प्रावधान संवैधानिक रूप से वैध हैं। अभिव्यक्ति की आजादी कोई असीम अधिकार नहीं है।'

बहरहाल, यहां यह भी याद रखना चाहिए कि 2020 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को उनके दो ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया, जिनमें उन्होंने न्यायपालिका की आलोचना की थी। इस फैसले की व्यापक आलोचना हुई, जिसमें इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरनाक प्रभाव डालने वाला बताया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस निर्णय पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि इससे न्यायपालिका की वैध आलोचना पर खौफनाक असर पड़ सकता है।

जनवरी 2023 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच–न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सरकार का आधिकारिक बयान नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की आवश्यकता नहीं है। यह मामला उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खान के एक बयान से संबंधित था, जिसमें उन्होंने एक आपराधिक घटना को राजनीतिक साजिश बताया था।

लब्बोलुआब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों से स्पष्ट होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है और इसे अन्य अधिकारों और समाज के हितों के साथ संतुलित किया जाना आवश्यक है। अदालत के फैसले इस संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, हालांकि इन निर्णयों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से बहस और आलोचना होती रही है। इससे इतर सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कभी काफी सख्त को कभी बेहद नरम नजर आता है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को भले ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई हो,लेकिन वह विवादित शेरों शायरी से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। कभी वह माफिया अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ने के चलते भी विवादों में रह चुके हैं।

शायरी के जरिये सियासत की दुनिया में दाखिल होने वाले इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ वर्ष पूर्व प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान खतरनाक गुंडे अतीक अहमद की जमकर तारीफ की थी। इमरान प्रतापगढ़ी, अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ते हुए कह रहे हैं कि,'इलाहाबाद वालों मेरी एक बात याद रखना, कई सालों तक कोई अतीक अहमद होगा। मुझे इस बात का अंदाजा है कि एक शख्स इस शहर में बैठा यही, जो सबकुछ संभाल लेगा।' प्रतापगढ़ी ऐसी ही शेरो शायरी माफिया मुख्तार अंसारी की शान में भी पढ़ चुके थे,जिसकी चंद लाइनों मे उन्होंने अपने को मुख्तार के रूप में पेश करते हुए कहा था,' एक पटाखा भी फोड़ा तो बम लिख दिया, जितनी मोहब्बत है इस मुल्क से, उससे कहीं ज्यादा मैं वफादार हूं। हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ।

घुसपैठियों के लिए आसान लांचिंग पैड

नेपाल बॉर्डर के मदरसे

सीमा खुली होने का फायदा उठाकर पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों सहित कई देशों के घुसपैठियें और आतंकवादी भारत में आते हैं और यहां आतंक फैलाते हैं। यही वजह है नेपाल और भारत के बीच की सीमा क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ सालों में खासी चिंता देखी गई है।

संजय सक्सेना, लखनऊ

पड़ोसी राज्य नेपाल, भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। वैसे तो नेपाल के भारत से हमेशा प्रगाण संबंध रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षो में चीन की भी दखलंदाजी वहां बढ़ी है। चीन के कई प्रोजेक्ट नेपाल में चल रहे हैं। भौगालिक रूप से देखा जाये तो चीन और नेपाल की सीमा 1439 किलोमीटर लम्बी है। वहीं भारत और नेपाल की सीमा की लम्बाई 1751 किलोमीटर है। यह सीमाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से जुड़ी हुई हैं। सबसे लम्बी सीमा 726 किलोमीटर बिहार से उसके बाद उत्तर प्रदेश से 551 और उत्तराखंड से 275 किलोमीट और पश्चिमी बंगाल से 100 एवं सिक्किम से 99 किलोमीटर तक जुड़ी हैं। कभी यह सीमाएं लगभग पूरी तरह से खुली रहती थीं, लोग आसानी से बिना वीजा और पासपोर्ट के एक–दूसरे देशों में आ जा सकते थे। दोनों देशों के बीच व्यापार करने पर भी कोई प्रतिबंद्ध

नहीं था,लेकिन अब हालात काफी बदल गये हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब इन सीमाओं को लांघकर अराजक तत्व और आतंकवादी ताकतें भी भारत में प्रवेश करने लगी हैं। सीमा खुली होने का फायदा उठाकर पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों सहित कई देशों के घुसपैठियें और आतंकवादी भारत में आते हैं और यहां आतंक फैलाते हैं। यही वजह है नेपाल और भारत के बीच की सीमा क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ सालों में खासी चिंता देखी गई है। सबसे खास बात यह है कि इन घुसपैठियों और आतंकवादियों के लिये भारत–नेपाल के बार्डर के बार्डर पर बने मदरसे सुरक्षित ठिकाना बन कर उभर रहे हैं। कई मदरसों के तार भारत विरोधी ताकतों के साथ जुडे हुए हैं।

नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों का बढ़ना और आतंकवादियों का घुसपैठ करने का प्रयास स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है। खासकर, 28 फरवरी को काठमांडू में हुई हिंसा ने इस क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है।यह हिंसा सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भारत में भी सुरक्षा के लिहाज से इसे गंभीर माना जा रहा हैं। नेपाल सीमा के पास रहने वाले एक पूर्व शिक्षक का कहना है कि हाल के दिनों में सरहदी क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों का बढ़ना चिंताजनक है। उनका मानना है कि पाकिस्तान और चीन द्वारा नेपाल सीमा को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड बनाने की साजिश चल रही है। उनका यह भी कहना है कि कुछ मजहबी शिक्षण संस्थानों में भारत से भागने वाले कुख्यात अपराधियों से लेकर

भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को भी शरण मिल रही है। बीते फरवरी महीने में सीमा से बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा गया था, जिसे नेपाली मदरसे में शरण मिली थी। यह घटना यह साबित करती है कि नेपाल में कुछ जगहें आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुके हैं। नेपाली सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि बांग्लादेश के एक आतंकवादी संगठन जमात–उल–मुजाहिदीन के आतंकवादी को नेपाल के सीमा क्षेत्र में पनाह दी गई थी। इसी तरह, अलकायदा इन इंडियन सब कांटिनेंट (एक्यूआईएस) जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन भी नेपाल के बदलते हालात का फायदा उठा सकते हैं। इन संगठनों का लक्ष्य भारत में घुसपैठ कर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना हो सकता है। इस संदर्भ में पूर्व आईबी अधिकारी प्रवीण गर्ग का कहना है कि काठमांडू में जो हिंसा हुई, वह नेपाल में राजाबादी आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश हो सकती है। उनके अनुसार, बांग्लादेश को अस्थिर करने के बाद, पाकिस्तान और चीन के सुरक्षा एजेंसियां नेपाल को भी अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। इन दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों की नेपाल में सक्रियता इस संभावना को और मजबूत करती है।

खासकर इस साल की शुरूआत से इन दोनों देश की एजेंसियों की भारत से सटे नेपाली क्षेत्र में बढ़ी सक्रियता एक गंभीर चिंता का विषय है। चौकाने वाली बात यह भी है कि जो नेपाल कुछ वर्षो तक हिन्दू राष्ट्र होता था,वहां अब शरिया कानून की मांग भी उठने लगी है, जो कि पहले नेपाल के मुसलमानों के लिए एक दूर का ख्वाब था। लेकिन अब इसे संसद में कुछ मुस्लिम सांसदों द्वारा उठाया गया है, जो इसे नेपाल के लिए एक नई राजनीतिक दिशा के रूप में देख रहे हैं। वैसे मुस्लिमों की बढ़ती आबादी और शरिया कानून की वकालत के बीच हिन्दू संगठन भी एक बार फिर से नेपाल को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की वकालत

नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों का बढ़ना और आतंकवादियों का घुसपैठ करने का प्रयास स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है। खासकर, 28 फरवरी को काठमांडू में हुई हिंसा ने इस क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। यह हिंसा सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भारत में भी सुरक्षा के लिहाज से इसे गंभीर माना जा रहा हैं।

करने लगे हैं। हालांकि, राजनीति के कई जानकार नेपाल में शरिया कानून की मांग को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा प्रायोजित किया हुआ कदम बता रहे है, जो नेपाल को राजनीतिक रूप से अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है। नेपाली सीमा पर बढ़ रही इन आतंकी गतिविधियों की ओर इशारा करते हुए आंकड़े भी सामने आए हैं, जो यह साबित करते हैं कि भारत में आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयास बढ़े हैं।

बात बार्डर पर चल रहे मदरसों की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्तता की कि जाये तो इसके कई केस मिल जाते हैं। इसी वर्ष के शुरूआती महीनों में मटर–धमऊर क्षेत्र के पिलर संख्या 501–6 के पास से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, जिसे मदरसा मदीनतुल में शरण मिली थी। इसी तरह, 2024 में हिजबुल मुजाहिद्दीन के तीन आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, जो नेपाली सीमा के पास स्थित एक मदरसे में ठहरे हुए थे। 2020 में पापलुर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक ट्रेनिंग कमांडर राशिद को गिरफ्तार किया गया था, जो नेपाल सीमा से सटे मदरसे में सक्रिय था। इस तरह की घटनाएं यह साबित करती हैं कि नेपाल सीमा पर आतंकवादियों की सक्रियता बढ़ रही है, और सुरक्षा एजेंसियों को इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। इसके लिये मदरसों के भी पेंच कसना जरूरी है।

गौरतलब हो, सुरक्षा एजेंसियों के पास भी नेपाल सीमा से जुड़ी एक लंबी सूची है, जिसमें विभिन्न आतंकवादियों की गिरफ्तारी का जिक्र है। 2015 में पाकिस्तानी वैज्ञानिक डॉ. जावेद को सोनौली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, जो नेपाल में ठहरे हुए थे। 2013 में आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया था, और इसी साल यासीन भटकल भी गिरफ्तार हुआ था। यही नहीं, 2010 में बढ़नी बॉर्डर से इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकवादी सलमान उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया था, जो एक नेपाली मदरसे में पनाह लिए हुए था। यह घटनाएं दर्शाती हैं कि नेपाल से घुसने वाले आतंकवादियों की संख्या समय के साथ बढ़ी है और सुरक्षा एजेंसियों को इस पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी के चलते भारतीय सुरक्षा बलों ने नेपाल से सटी सीमा पर गश्त बढ़ा दी है और इन क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, नेपाल में इन आतंकवादियों की गतिविधियों को लेकर पूरी तरह से नियंत्रण पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि नेपाल के अंदर भी कई मदरसे और धार्मिक संस्थान आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन चुके हैं। इन आतंकवादी समूहों के पास न सिर्फ भारतीय बल्कि नेपाली क्षेत्र में भी अपनी जड़ें फैलाने की क्षमता है,जो दोनों ही मुल्कों के लिये बड़े खतरे का संकेत है। समय रहते नेपाल सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाये तो दिन पर दिन हालात और भी खराब होते जायेगे। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि नेपाल और भारत दोनों देश मिलकर सीमा पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करें और आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल सीमा पर बढ़ती आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ के प्रयासों के बीच दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच समन्वय और सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, नेपाल को अपने आंतरिक सुरक्षा उपायों को भी मजबूत करना होगा ताकि वह आतंकवादियों की गतिविधियों को अपनी सीमा से बाहर रख सके और भारतीय

तीन साल में यूपी से खत्म हो जाएगी गरीबीः योगी

यह बात उन्होंने तब कही जब एक सप्ताह पहले ही उनका बयान आया था कि वे राजनीति में लंबी पारी खेलने नहीं आए हैं। लेकिन उनके इस नए संकल्प से साफ है कि वे अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं।

अजय कुमार, लखनऊ

गरीबी हटाओ का नारा भारतीय राजनीति का सबसे पुराना और सबसे आजमाया हुआ वाक्य है। यह नारा सुनते–सुनते कई पीढ़ियां जवान हो चुकी हैं, लेकिन गरीबी का अंत अब तक नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने इस नारे को 1971 में दिया था और इसी नारे पर चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी थीं। उसके बाद से लेकर आज तक हर सरकार ने इस नारे को अपनी सुविधा और राजनीतिक जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी ने भी गरीबी को जातीय राजनीति के जवाब के रूप में पेश किया, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यह संकल्प लिया है कि वे उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त राज्य बनाएंगे। यह दावा उन्होंने महाराजगंज में किया, जहां उन्होंने कहा कि अगले तीन साल में यूपी से गरीबी खत्म कर दी जाएगी और प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाया जाएगा। यह बात उन्होंने तब कही जब एक सप्ताह पहले ही उनका बयान आया था कि वे राजनीति में लंबी पारी खेलने नहीं आए हैं। लेकिन उनके इस नए संकल्प से साफ है कि वे अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं।

योगी आदित्यनाथ ने जो संकल्प लिया है, वह सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं बल्कि व्यक्तिगत संकल्प बताया जा रहा है। उन्होंने खुद कहा है कि राजनीति में भी समयसीमा होनी चाहिए और इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने तीन साल की डेडलाइन तय की है। हालांकि तकनीकी रूप से उनके मौजूदा कार्यकाल के सिर्फ दो साल ही बचे हैं, इसलिए यह मानना मुश्किल नहीं कि उनका इरादा 2027 के बाद भी सत्ता में बने रहने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह योगी आदित्यनाथ भी श्गरीबश को एक अलग वर्ग के रूप में पेश कर रहे हैं। जब बिहार में जातिगत जनगणना के बाद मोदी ने ओबीसी, एससी, एसटी और श्गरीबश का नाम लिया था, तो उसी श्गरीबश वर्ग को अब योगी राजनीति का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए गरीबी हटाओ का अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण है। लेकिन

योगी सरकार ने इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती पर की, जब उन्होंने 'जीरो पॉवर्टी स्टेट' बनाने का ऐलान किया। सरकार के मुताबिक प्रदेश के हर ग्राम पंचायत से 25 निर्धनतम परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की 17 योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 तक पहुंचाया जाए ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। इसके लिए सरकार खाद्यान्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की योजनाओं को समन्वयित रूप से उन तक पहुंचाएगी।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2013–14 में बहुआयामी गरीबी का स्तर 42.59 प्रतिशत था, जो 2022–23 में घटकर 17.40 प्रतिशत पर आ गया है। इसका अर्थ है कि बीते नौ वर्षों में करीब 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह आंकड़ा बताता है कि सरकार की योजनाएं कुछ हद तक असरदार रही हैं। लेकिन यूपी जैसे विशाल और विविध राज्य में गरीबी पूरी तरह मिटाना अब भी एक बड़ा लक्ष्य है। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, उनकी सरकार ने पिछले छह वर्षों में 55 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत घर दिए हैं। इसके अलावा तीन करोड़ से अधिक परिवारों को शौचालय की सुविधा दी गई है और लगभग सभी गांवों को बिजली और पानी की सुविधा से जोड़ा गया है।

सरकार का दावा है कि वह रोजगार को प्राथमिकता पर रख रही है। 'मिशन रोजगार' अभियान के तहत सरकार अगले तीन–चार वर्षों में दो करोड़ युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के तहत 7.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे अपनी आजीविका कमा सकें। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के युवाओं को सीधा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। वहीं, मनरेगा जैसी योजनाएं भी ग्रामीण रोजगार सृजन में मदद कर रही हैं।

हालांकि योगी आदित्यनाथ का ये संकल्प विपक्षी दलों को रास नहीं आया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने इसे सिर्फ चुनावी स्टंट करार दिया है।

उत्तर प्रदेश की सरकार दावा कर रही है कि वह अब गरीबी के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। यह संकल्प सिर्फ सरकारी दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे मिशन मोड में लागू किया जाएगा। सरकार के अनुसार 2025 तक प्रदेश के सभी ब्लॉकों में गरीबी निवारण की प्रगति का ऑडिट किया जाएगा और 2026 तक अधिकांश चयनित परिवार गरीबी से ऊपर उठ चुके होंगे।

हालांकि योगी आदित्यनाथ का ये संकल्प विपक्षी दलों को रास नहीं आया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने इसे सिर्फ चुनावी स्टंट करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने पहले भी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े वादे किए, लेकिन उनके परिणाम जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। विपक्ष का तर्क है कि अगर सरकार वास्तव में गंभीर होती तो अब तक प्रदेश की सामाजिक सूचकांक में और सुधार दिखता। उदाहरण के तौर पर, एनएफएचएस–5 के मुताबिक प्रदेश में अभी भी कुपोषण, एनीमिया और शिशु मृत्यु दर जैसे आंकड़े चिंता का विषय हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का दावा है कि वह प्रदेश को गरीबी मुक्त बना देंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की आबादी, संसाधनों की कमी, और प्रशासनिक भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां इस अभियान को कठिन बनाती हैं। साथ ही प्रदेश के पिछड़े जिलों, जैसे बलिया, श्रावस्ती, सोनभद्र और चंदौली में अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में अगर सरकार वास्तव में गरीबी खत्म करना चाहती है, तो उसे सिर्फ योजनाएं बनाने से आगे जाकर जमीनी कार्यवाही करनी होगी।

फिलहाल, यूपी सरकार ने जिन योजनाओं की घोषणा की है, वे यदि ईमानदारी से लागू की जाती हैं तो परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं। लेकिन इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्थानीय प्रशासन कितना सजग और जवाबदेह रहता है। भ्रष्टाचार, लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी समस्याएं पहले भी कई सरकारी प्रयासों को विफल कर चुकी हैं।

योगी आदित्यनाथ के संकल्प को राजनीति से जोड़कर देखने के भी कारण हैं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि राजनीति में समय सीमा होनी चाहिए, लेकिन अगर वे इस संकल्प को 2027 तक भी पूरा करना चाहते हैं तो जाहिर है कि उनका इरादा अगला चुनाव जीतने और सत्ता में बने रहने का है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर वे यूपी मॉडल को प्रस्तुत करने की तैयारी में हैं, लेकिन विकास के मानकों पर यूपी को गुजरात जैसा बनाना आसान नहीं है।

बहरहाल, यह कहना गलत नहीं होगा कि ग़रीबी हटाओ का नारा एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार इसे सिर्फ नारे तक सीमित रखने से न तो जनता का भला होगा, न ही योगी आदित्यनाथ की राजनीति को स्थायित्व मिलेगा। अगर वे अपने इस वादे को सच साबित करते हैं तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर वाकई बदल सकती है और यूपी मॉडल एक नई मिसाल बन सकता है। लेकिन अगर यह भी एक और राजनीतिक हथियार बनकर रह गया, तो जनता का भरोसा और भी डगमगाएगा। इसीलिए यह समय वादों से आगे बढ़कर उन्हें निभाने का है। यह योगी आदित्यनाथ के लिए सिर्फ एक संकल्प नहीं, बल्कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन

भीख मांगकर देश चला रहे पाकिस्तानी भारत से नफरत नहीं उससे बराबरी करें

पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री या सेना प्रमुख हुए वह भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलते और आतंकवादियों को संरक्षण देते रहें। आज भी यह सिलसिला जारी है।

अजय कुमार, लखनऊ

1947 में पाकिस्तान की बुनियाद हिन्दुओं से नफरत के कारण पड़ी थी। आज करीब 77 वर्षो के बाद भी पाकिस्तान हिन्दुओं के प्रति ऐसा ही रवैया लेकर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री या सेना प्रमुख हुए वह भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलते और आतंकवादियों को संरक्षण देते रहें। आज भी यह सिलसिला जारी है। इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए पाक की फौजी हुकूमत एक बार फिर पुराना राग अलाप रही है। इस्लामाबाद में हाल ही में हुए प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर के मुद्दे पर उकसाने वाले बयान दिए, जिनसे न केवल क्षेत्रीय शांति को नुकसान हुआ है, बल्कि यह भी साफ हो गया कि पाकिस्तान की सत्ता संरचना अब भी नफरत और विघटन की राजनीति को अपनी ताकत मानती है। मौजूदा जनरल मुनीर का हाल ही में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की श्गले की नसश बताया,ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। यही सब पिछले कई दशकों से पाकिस्तान की फौजी हुकूमत द्वारा लगातार दोहराया जाता रहा है। पाकिस्तान के जनरल यह हमेशा कहते रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसे कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन क्या इस विचारधारा ने पाकिस्तान को किसी प्रकार का लाभ पहुंचाया है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, आतंकवाद की पोषक छवि बन चुकी है और वैश्विक मंच पर वह अलग–थलग पड़ा हुआ है।

पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इन्हीं हरकतों के कारण वह आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के शुरुआती महीनों में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार महज 3.1 अरब डॉलर था, जो मुश्किल से कुछ हफ्तों का आयात खर्च चला सकता है। महंगाई दर 30 प्रतिशत के पार जा चुकी है, बेरोजगारी करीब नौ प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और जनता राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से त्रस्त है। ऐसे में पाकिस्तान की फौजी हुकूमत का इस प्रकार का उकसावे भरा बयान यह दर्शाता है कि पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है, सिवाय इसके कि वह अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पुराने और साम्प्रदायिक मुद्दों को उछाले।

बलूचिस्तान में अलगाववाद की लपटें तेज होती जा रही हैं, और वहां के लोग पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे पाकिस्तान के भीतर की अस्थिरता को और भी बढ़ावा मिला है। जनरल मुनीर का यह कहना कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अभिमान है और कोई इसे नहीं छीन सकता, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उन्हें बलूचिस्तान की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता है। पाकिस्तान के भीतर के लोग यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक कश्मीर के नाम पर उन्हें गुमराह किया जाएगा, जब उनके घरों में रोटियां पकने की स्थिति नहीं है? यह सवाल पाकिस्तान की युवा पीढ़ी में और सोशल मीडिया पर गहराई से उठ रहा है, जहां सेना की आलोचना अब आम बात हो गई है। कई लोग खुलकर कह रहे हैं कि भारत के साथ फिर से मिल जाना ही बेहतर होता, जो एक संकेत है कि पाकिस्तान में अब लोग अपनी असल समस्याओं के बारे में गंभीर हो रहे हैं।

जनरल मुनीर ने अपने भाषण में विदेशों में बसे पाकिस्तानियों से अपील की कि वे अपने बच्चों को यह सिखाएं कि पाकिस्तान क्यों बना और हिंदू और मुसलमान कभी एक जैसे नहीं हो सकते। उनका यह बयान पाकिस्तान की संस्कृति और पहचान को हिंदुओं से श्रेष्ठ बताने वाला था, जबकि आज की वैश्विक दुनिया में यह सोच पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है। टू नेशन थ्योरी, जिसकी नींव पर पाकिस्तान बना था, वह 1971 में ही धराशायी हो गई थी, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह विभाजन यह साबित करता है कि धर्म के आधार पर बनी राष्ट्र की अवधारणा टिकाऊ नहीं हो सकती, और पाकिस्तान की असफलता इस सिद्धांत का प्रमाण बन चुकी है

आज बलूच, सिंधी और पख्तून समुदाय भी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जनरल मुनीर को यह डर सता रहा है कि अगर उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ नफरत का एजेंडा नहीं चलाया, तो पाकिस्तान की नई पीढ़ी उनसे सवाल पूछेगी। इसलिए वह कमजोर और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को एक बार फिर दुश्मन के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में बचे–खुचे हिंदू समुदाय की स्थिति बेहद दयनीय है। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23 प्रतिशत थी, जो आज घटकर महज 3 प्रतिशत रह गई है। या तो वे पलायन कर गए, मारे गए, या फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिए गए। फिर भी, जनरल मुनीर को इनसे डर क्यों लगता है? क्योंकि वह जानते हैं कि यदि नफरत का यह माहौल समाप्त हो गया, तो पाकिस्तान के सत्ता ढांचे की बुनियाद हिल जाएगी।

पाकिस्तान की मशहूर सीरीज जिंदगी गुलजार है में भी यह दिखाया गया था कि पाकिस्तान में हिंदुओं को किस प्रकार हाशिए पर रखा जाता है, और यह किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अल्पसंख्यक समुदाय पहले से ही इतना शोषित है, तो उनके खिलाफ नफरत फैलाने की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है? अंतरराष्ट्रीय पत्रकार और न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक ताहा सिद्दीकी ने एक्स पर लिखा था कि जनरल असीम मुनीर बच्चों के दिमाग में जहरीली सोच भरना चाहते हैं ताकि उनका ब्रेनवॉश किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुनीर दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, जो 1971 में ही असफल हो चुका था। यह बयान यह दर्शाता है कि जनरल मुनीर पाकिस्तान के भीतर की अस्थिरता और विघटन को लेकर बेहद चिंतित हैं।

परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने कारगिल युद्ध छेड़कर भारत से सीधा टकराव किया था, उन्होंने भी कश्मीर को हथियाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने आतंकवाद को राज्य नीति का हिस्सा बनाया और भारत में कई आतंकवादी हमले कराए थे। अब जनरल मुनीर भी वही भाषा बोल रहे हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान फिर से वही आत्मघाती रास्ता अपनाना चाहता है? पाकिस्तान अब कमजोर है, लेकिन उसकी सेना और खुफिया एजेंसियां अभी भी आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करती रहेंगी। जम्मू–कश्मीर में हालिया समय में आतंकवादी गतिविधियों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन यह मानना भूल होगी कि खतरा पूरी तरह से टल गया है। भारत को पाकिस्तान की असलियत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उजागर करते रहना चाहिए। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को भी भारत में पुनः शामिल करने की दिशा में कूटनीतिक प्रयास तेज किए जाने चाहिए। भारत को दुनिया को यह दिखाना होगा कि वह शांति चाहता है, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा भी जानता है। जहां तक पाकिस्तान की बात है,वह 77 साल तक भारत से दुश्मनी का नतीजा देख चुका है, अच्छा होगा कि पाकिस्तान, भारत से लड़ने झगड़ने

बिहार में लालू परिवार से हटकर राहुल तैयार कर रहे हैं कांग्रेस की सियासी जमीन

सरकार बनाने के लिये एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ-साथ मैदान में जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और ओवैसी भी अपना भविष्य तलाश रहे हैं।

संजय सक्सेना, लखनऊ

विधानचुनाव की घड़ी करीब आती जा रही है। चंद महीनों बाद यहां नई सरकार का गठन होना है। सरकार बनाने के लिये एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ–साथ मैदान में जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और ओवैसी भी अपना भविष्य तलाश रहे हैं। बिहार में अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर एनडीए ने तो साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन या महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बीच भावी सीएम को लेकर कोई नाम नहीं तय हो पाया है, जबकि आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। यह सब तब देखने को आ रहा है जबकि कांग्रेस और राजद के बीच रिश्ता दशकों पुराना है। मगर अब लगता है कि दोनों ही दल इसे आगे बढ़ाने के मूड में नहीं हैं। इसी के चलते मौजूदा दौर में यह गठबंधन एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। लालू यादव और सोनिया गांधी की दोस्ती ने वर्षों तक दोनों दलों के संबंधों को मजबूती दी, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जबसे राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ली हैं, तबसे यह रिश्ता लगातार खिंचाव का शिकार होता जा रहा है। यह खिंचाव केवल राजनीतिक फैसलों में नहीं, बल्कि वैचारिक टकराव और नेतृत्व के बीच भरोसे की कमी में भी दिखाई देता है।

सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी के समानांतर कांग्रेस के एक नेता को उभारना चाह रहे हैं। राहुल गांधी का कन्हैया कुमार को बिहार में आगे करना और समय–समय पर उनका साथ देना, आरजेडी को साफ तौर पर चुभता है। लालू यादव को यह

डर सताता है कि कांग्रेस कहीं उनके यादव वोट बैंक में सेंध न लगा ले, और यही डर तेजस्वी यादव के व्यवहार में भी झलकता है। तेजस्वी खुद को बिहार की राजनीति में एकमात्र विकल्प के रूप में स्थापित करने में लगे हैं, और ऐसे में कन्हैया कुमार जैसे नेताओं का उभार उन्हें असहज कर देता है। यह असहजता सिर्फ जातिगत समीकरणों की वजह से नहीं है, बल्कि कांग्रेस की बदली हुई रणनीति का संकेत भी देती है, जिसमें वह अब खुद को हर वर्ग में स्वीकार्य बनाना चाहती है, चाहे वह सवर्ण हों, दलित हों या यादव।

लेकिन समस्या यह है कि लालू यादव कांग्रेस को सवर्णों की राजनीति करने से नहीं रोकते, लेकिन जैसे ही कांग्रेस बिहार के यादव या दलित वोट बैंक में हाथ डालती है, उन्हें परेशानी होने लगती है। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ये दोनों चेहरे लालू यादव के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं।

खासकर तब, जब ये दोनों नेता सामाजिक न्याय की वही भाषा बोलते हैं जिसे लालू यादव ने दशकों पहले गढ़ा था। पप्पू यादव का क्षेत्रीय प्रभाव और कन्हैया कुमार की वैचारिक पकड़, दोनों ही आरजेडी को अस्थिर कर सकते हैं और राहुल गांधी का इन दोनों को प्रमोट करना, आरजेडी को यह समझाने का संकेत है कि कांग्रेस अब सिर्फ सहायक दल बनकर नहीं रहना चाहती, लेकिन यह टकराव सिर्फ वैचारिक या जातिगत नहीं है, बल्कि नेतृत्व के सवाल पर भी है। कांग्रेस बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने से कतरा रही है, जबकि आरजेडी स्पष्ट रूप से यह ऐलान कर चुकी है। तेजस्वी

सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी के समानांतर कांग्रेस के एक नेता को उभारना चाह रहे हैं। राहुल गांधी का कन्हैया कुमार को बिहार में आगे करना और समय-समय पर उनका साथ देना, आरजेडी को साफ तौर पर चुभता है। लालू यादव को यह डर सताता है कि कांग्रेस कहीं उनके यादव वोट बैंक में सेंध न लगा ले, और यही डर तेजस्वी यादव के व्यवहार में भी झलकता है।

की अगुवाई में महागठबंधन की बैठकें हो रही हैं, कोआर्डिनेशन कमेटी बनी है और सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे चुनावी रणनीति उनके नेतृत्व में ही तैयार हो रही हो। लेकिन कांग्रेस का यह मानना कि तेजस्वी का नाम सामने लाकर चुनाव लड़ने से दलित, सवर्ण और गैर–यादव पिछड़ा वर्ग उनके साथ नहीं आएगा, यह दिखाता है कि दोनों दलों की सोच में गहरा फासला है। यह वही कांग्रेस है जिसने कभी लालू यादव के भ्रष्टाचार मामलों में फंसे होने के बावजूद खुलकर उनका समर्थन किया था, लेकिन अब वह अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाना चाहती है। राहुल गांधी की रणनीति यह है कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं घोषित कर इंडिया गठबंधन ने लड़ा, वैसे ही बिहार में भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना रहे ताकि सभी जातियों और वर्गों के वोट एक साथ जोड़े जा सकें। लेकिन लालू और तेजस्वी के लिए यह रणनीति उनकी स्वीकार्यता और नेतृत्व क्षमता पर सीधा सवाल है।

गौरतलब है लालू यादव हमेशा से अपने मुस्लिम–यादव समीकरण पर भरोसा करते रहे हैं, और इसी समीकरण को बचाए रखने के लिए वे कांग्रेस को इस दायरे में आने से रोकना चाहते हैं। 2019 में जब कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा किशनगंज से जीत गया, और 2020 में कांग्रेस के चार मुस्लिम विधायक विधानसभा में पहुंचे, तो यह आरजेडी के लिए एक तरह की चेतावनी थी। आरजेडी चाहती है कि मुस्लिम वोट पूरे तौर पर उनके पास रहें, लेकिन कांग्रेस के सक्रिय होने से इस समीकरण में दरार आने लगी है। बात यहीं तक सीमित नहीं है राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर भी लालू यादव की नाराज हैं। वे चाहते थे कि अध्यक्ष वही बने जो उनके करीब हो, लेकिन राहुल गांधी ने राजेश को चुना जो दलित समाज से आते हैं और कांग्रेस को इस वर्ग में पैठ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव की आपत्ति इस बात पर है कि कांग्रेस अगर दलित और यादव, दोनों वोट बैंक में सेंध लगाने लगी तो आरजेडी की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? राहुल गांधी का जातिगत जनगणना पर आक्रामक रुख भी लालू यादव को अखरता है।

लालू खुद कास्ट सेंसस के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं, और जब राहुल गांधी ने बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातीय गणना को फर्जी बता दिया था, तब यह एक सीधी चुनौती की तरह लगा। यह बयान, उस वक्त आया जब आरजेडी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही थी, और महागठबंधन इसे प्रचारित कर रहा था। यह और बात है कि राजद इस पर खुलकर नहीं बोल रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव चाहे जितना भी दावा करें कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है, लेकिन सच यही है कि महागठबंधन एक बेहद असहज समझौते पर चल रहा है। कांग्रेस का अंदरखाने यह मानना है कि तेजस्वी की स्वीकार्यता सीमित है, और अगर वे चेहरा बनते हैं, तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि चुनाव में चेहरा न हो,ताकि जरूरत के हिसाब से निर्णय लिया जा सके। यह रणनीति जहां एक ओर कांग्रेस के लिए सुरक्षित है, वहीं आरजेडी को असुरक्षित

राहुल गांधी की विदेश में जहरीली जुबान, भारत की साख पर वार

अमेरिका यात्र के दौरान बोस्टन यूनिवर्सिटी में दिए गए उनके बयान ने सियासी हलकों में एक बार फिर उबाल ला दिया है। राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग पर समझौता करने का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र में हुए चुनावों में धांधली हुई थी।

संजय सक्सेना, लखनऊ

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी धरती से भारत की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर विवादों में आ गए हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान बोस्टन यूनिवर्सिटी में दिए गए उनके बयान ने सियासी हलकों में एक बार फिर उबाल ला दिया है। राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग पर समझौता करने का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र में हुए चुनावों में धांधली हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उनके सहयोगियों को जिताने के लिए चुनाव आयोग ने पक्षपात किया।

राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और अब वे अमेरिका जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यह क्यों भूल जाते हैं कि उसी समय झारखंड में भी चुनाव हुए थे, और वहां कांग्रेस व सहयोगियों की सरकार बनी थी। क्या वहां भी चुनाव आयोग से कोई समझौता हुआ था?

संबित पात्रा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस का हवाला देते हुए कहा कि दोनों 50 हजार के मुचलके पर जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग खुद भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हैं, वे विदेशी धरती पर जाकर भारत को अपमानित कर रहे हैं। पात्रा ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट के अनुसार 988 करोड़ रुपये का फर्जी डोनेशन राहुल और सोनिया गांधी की जेब में गया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर श्चोर मचाए शोरश की नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पूरे देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है।

पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नेता दावा करते हैं कि कोई संपत्ति बेची या ट्रांसफर नहीं की गई, इसलिए गड़बड़ी कैसे हुई? लेकिन ईडी की चार्जशीट में साफ कहा गया है कि एजेएल (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) की संपत्तियों का उपयोग समाचार पत्र कार्यालयों के रूप में नहीं बल्कि 'अपराध की आय' के रूप में किया गया। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस, लखनऊ और भोपाल की प्राइम लोकेशन वाली संपत्तियों का हवाला देते हुए पात्रा ने कहा कि ये संपत्तियां पत्रकारिता के लिए नहीं बल्कि लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल की गईं।

राहुल गांधी के विदेश में भारत के खिलाफ दिए गए बयानों की सूची लंबी होती जा रही है। मार्च 2023 में ब्रिटेन

सतंबर 2024 में अमेरिका के टेक्सास और वाशिंगटन डीसी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने में घबराहट होती है। इस बयान को भाजपा ने झूठा और भयावह करार दिया था।

दौरे पर उन्होंने कैंब्रिज विश्वविद्यालय में "लर्निंग टू लिसन इन द 21स्ट सेंचुरी" विषय पर व्याख्यान देते हुए भारत में लोकतंत्र के खतरे की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत की सभी स्वतंत्र संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। उनके इस बयान पर दिल्ली में एक वकील ने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी।

सितंबर 2024 में अमेरिका के टेक्सास और वॉशिंगटन डीसी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने में घबराहट होती है। इस बयान को भाजपा ने झूठा और भयावह करार दिया था। उस दौरे पर राहुल गांधी ने चीन की नीतियों की प्रशंसा भी की थी, जिसे भाजपा ने भारत विरोधी करार दिया। उन्होंने अमेरिका में भारत विरोधी छवि वाले नेताओं जैसे इल्हान उमर से भी मुलाकात की, जिस पर विवाद हुआ।

जून 2023 में वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को 'धर्मनिरपेक्ष' पार्टी बताया था। भाजपा ने इस पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने इसे देश के बंटवारे का बीज बोने वाला बयान बताया। इससे पहले भी, 2018 में सिंगापुर और बहरीन दौरे पर उन्होंने भारत के खानपान की स्वतंत्रता को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में यह तय नहीं किया जा सकता कि लोग क्या खाएं। उस समय देश में बीफ को लेकर चल रहे विवाद के बीच यह बयान और भी ज्यादा चर्चा में आया।

मई 2022 में लंदन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय विदेश सेवा को "अहंकारी" बताया था। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखा पलटवार करते हुए कहा था कि यह अहंकार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। उन्होंने राहुल के बयान को भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठा को कमजोर करने वाला करार दिया था।

इन सभी घटनाओं को मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी पर यह आरोप लगातार लगता रहा है कि वे विदेश जाकर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी देश में नहीं बल्कि विदेश में बैठकर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी यह भी कहती है कि भारत के लोकतंत्र की मजबूती का परिचय दुनिया को बार–बार देना पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेता विदेशी मंचों पर भारत को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

भाजपा की यह भी मांग रही है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भारत की प्रतिष्ठा को वैश्विक मंच पर नुकसान न हो। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही है, चाहे मंच देश का हो या विदेश का। यह सियासी खींचतान फिलहाल थमने वाली नहीं लगती, खासकर तब जब देश एक और चुनावी दौर की तरफ

सरकार ने ऑनलाइन स्कैम पर कसा शिकंजा चार मोर्चों पर लिया एक्शन

देशभर में केदारनाथ, वैष्णो देवी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा, होटल व कैब बुकिंग और हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर बढ़ रही ऑनलाइन धोखाधड़ी पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के माध्यम से चार स्तरों पर कार्रवाई तेज कर दी है। फर्जी वेबसाइटें, जो अधिकृत साइटों से मिलते-जुलते नाम और डिजाइन रखती हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया और सर्च इंजन पर पेड विज्ञापनों के जरिये लोगों को झांसे में ले रही हैं। जैसे ही लोग भुगतान करते हैं, संपर्क नंबर बंद या 'आउट ऑफ रीच' हो जाते हैं।

फर्जी लिंक और विज्ञपन होगे पहचान के दायरे में

सरकार ने गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर "स्कैम सिग्नल एक्सचेंज" की प्रक्रिया तेज की है ताकि फर्जी विज्ञापनों और वेबसाइटों की पहचान कर उन्हें रोका जा सके। धोखाधड़ी के अधिक मामले वाले क्षेत्रों में प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई है और नकली वेबसाइटों व पेमेंट गेटवे को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

चार स्तरों पर हो रही कार्रवाई

- स्कैम सिग्नल एक्सचेंजः गूगल, वॉट्सऐप, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स से नियमित रूप से धोखाधड़ी के संकेत साझा कर कार्रवाई।
- प्रवर्तनः संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां निगरानी और कानूनी कार्रवाई।
- साइबर पेट्रोलिंगः फर्जी वेबसाइटों और विज्ञापनों की पहचान कर उन्हें हटाना।
- रिपोर्टिंग सुविधाः साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www-cybercrime-gov-in) और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर त्वरित शिकायत और कार्रवाई की व्यवस्था।

ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए अपनाएं ये 5 जरूरी उपाय

- केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का उपयोग करेंरू बुकिंग या खरीदारी करते समय केवल प्रमाणिक और सरकारीध्मान्य वेबसाइट्स जैसे -gov-in या कंपनी के असली डोमेन का उपयोग करें।
- अज्ञात लिंक और कॉल से बचेंरू ईमेल,ैडै या सोशल मीडिया पर आए अनजान लिंक या फत कोड पर क्लिक न करें।
- सोशल मीडिया विज्ञापनों से सतर्क रहेंरू आकर्षक ऑफर्स वाले फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहें और बिना सत्यापन के भुगतान न करें।
- साइबर सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करेंरू मोबाइल और कंप्यूटर में एंटी-वायरस, फायरवॉल और सुरक्षित ब्राउजिंग एक्सटेंशन लगाएं।
- संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करेंरू किसी स्कैम का शिकार होने पर www-cybercrime-gov-in पर शिकायत दर्ज करें या 1930 पर कॉल करें।

मेरा पन्ना

मातृ दिवस पर विशेष
एक पाती माँ के नाम

माँ

ममता नेह समर्पण सौरभ महके जिसके प्यार में।।
रिश्ता माँ से बढ़कर कोई और नहीं संसार में।।

हमने जिसमें आँखें खोली।
वो थी माँ आँचल की झोली।
कर मधुमय पय-पान वहीं पर,
सीखी हमने पहली बोली।

घुटनों के बल दौड़ उसे दौड़ाया आँगन द्वार में.....
रिश्ता माँ से बढ़कर कोई और नहीं संसार मे....

रीझा करती है बचपन पर।
खीझा करती नटखटपन पर।
भर जाती मातृत्व गर्व से,
अपने देह-अंश युवपन पर।

संस्कार की शिक्षा देती जीवन के व्यवहार में.....
रिश्ता माँ से बढ़कर कोई और नहीं संसार में....

जाने कितनी पीर सही है।
माँ ने पर कब किसे कही है।
हम बोले यदि कभी सामने,
विहँस मौन माँ खड़ी रही है।

उसने सारे दर्द छुपाये मन के सुप्तागार में...
रिश्ता माँ से बढ़कर कोई और नहीं संसार में...

अब शायद हम बड़े हुए हैं।
सोच रहे खुद खड़े हुए हैं।
घोंट गला माँ अरमानों का,
बेघर करने अड़े हुए हैं।

फिर भी स्वर आशीष भरे हैं इन सबके प्रतिकार में..
रिश्ता माँ से बढ़कर कोई और नहीं संसार में....

छोड़ गई हो माँ बचपन में।
याद शेष बस रहती मन में।
जिनके सिर साया है माँ का,
समझो स्वर्ग बसा आँगन में।

माँ ईश्वर का रूप छाँव बरगद सी है परिवार में...
रिश्ता माँ से बढ़कर कोई और नहीं संसार में...

कल्याण गुर्जर "कल्याण"

कवयित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव प्रज्ञाञ्जलि

माँ

माँ इबादत है पूजा है
माँ भगवान का नाम दूजा है
माँ ममता का झरना है
माँ की दुआओं में ही फूलना फलना है
माँ आशाओं का पलना है
माँ के आशीर्वाद से ही जीवन भर चलना है
माँ की लोरी में सुकून है
माँ चंदन है, कुमकुम है, प्रसून है
माँ श्रद्धा है, त्याग है, तपस्या है
माँ बाधाओं में भी हिम्मत का हिस्सा है
माँ के आँचल में ममत्व का अहसास है
माँ संवेदना है, भावना है, विश्वास है
माँ के हाथों में बहुत स्वाद है
माँ बिन बोले ही समझ जाती सब राज है
माँ गीता है, वेद है, कुरान है
माँ हर समस्या का समाधान है
माँ शगुन है, आरती है
माँ जीवन को संवारती है
माँ साहस है, शक्ति है
माँ ईश्वर की भक्ति है
माँ कुदरत की अनमोल प्रति है
माँ का बिछुड़ना, सबसे बड़ी क्षति है
माँ का बिछुड़ना, सबसे बड़ी क्षति है

RNI No. UTTHIN/2021/80704

प्रकाशन की तिथि- प्रत्येक माह की 7 तारीख
प्रेषण दिनांक- प्रत्येक माह की 10 तारीख

विभिन्न विषयों पर आधारित हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

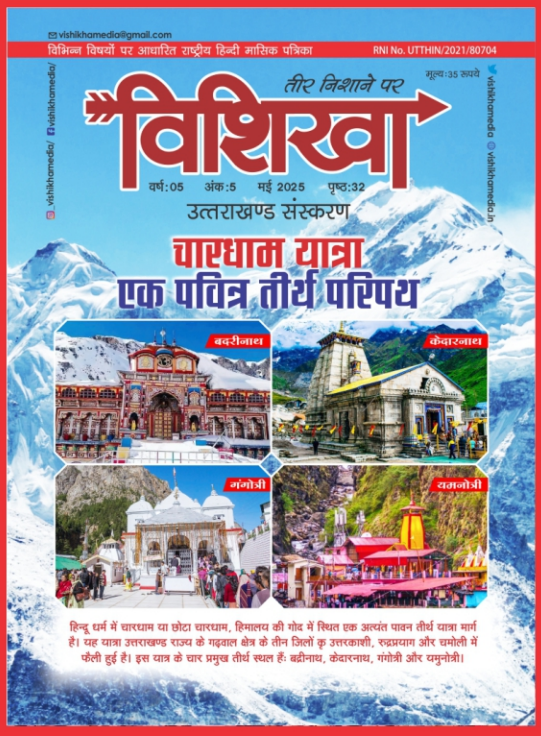

राजस्थान की राजधानी जयपुर एवं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाद विशिखा

अब शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी प्रकाशित...

मुख्यालय : विशिखा मीडिया 191/56, सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर
जयपुर-302033 (राज.)
Contact us: +911413562171, 9587455444
E-mail: vishikhamedia@gmail.com | Website: www.vishikhamedia.in
vishikhamedia/ _vishikhamedia/ vishikhamedia

विशिखा तीर निशाने पर